policy for the administration of prisons. This Committee has been set up to undertake a thorough probe into the functioning of prisons and to suggest measures as are considered necessary to bring about improvements. Also Sir, at the first instance the Committee has taken up the problems of Tihar Central Jail and a report has been submitted as an interim report with particular reference to the Tihar

श्री डी पी यदव : क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जेल में जो खादा सामग्री खरीदी जाती है वह किस भाव खरीदी जाती है ? इस संबंध में मैं एक उदाहरण बिहार का देना चाहता हूं। बिहार की जेलों में दूध 70 पैसे प्रति किलो खरीदा जाता है । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि 70 प्रति किलो खरीदा हुग्रा दूध, दूध होता है या पानी?

म्रह्यक्ष महोदय । म्राप तो तिहाड से बिहार पहुंच गये।

श्री डी पी० यत्वव : वहां पर दूध क्या भाव खरीदा जा रहा है, कम से कम यही बता दें।

ग्रध्यक्ष महोच : तिहार ग्रीर बिहार में "रे" तो ग्राखिर में ग्राता है।

श्री डी॰ पी यादव : बिहार से तिहाड़ तक एक ही हालत हो रही है।

Deaths of undertrial prisoners in States

\*188. SHRI RAJESH KUMAR SINGH:

> SHRI GHULAM RASOOL KOCHACK.

Will the Minister of HOME AFF-AIRS be pleased to state:

(a) whether many State Governments do not take care of the undertrials in their States;

- (b) if so, whether the Centre has shown and expressed its concern over the increasing number of deaths of undertrial prisoners;
- (c) whether Government had asked the State Governments to forward the list of undertrials who died between January, 1981 and May, 1982 in the States.
- (d) if so whether complete lists from all the State Governments have been received with full details of reasons; and
- (e) the action taken by Government thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) to (e). A statement giving the requisite information is attached.

## Statement

- (a) The subject 'Prisons' is included in the State List. Maintenance of prisoners is, therefore the responsibility of the States/Union Territories and there is no reason to believe that they do not take care of them.
- (b) Government of India do not have information to show that the number of deaths of undertrial prisoners is increasing
- (c) Yes, Sir. The information was called for from States/Union Territories for the period from January, 1981 to March, 1982.
- (d) No. Sir. The information is still awaited from 7 States and one Union Territory viz. Bihar, Jammu and Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, Meghalaya Punjab and Mizoram.
- (d) The State Governments and Union Territory Administrations follow the procedures prescribed in their respective Jail Manuals with regard to death of prisoners in different circumstances

JULY 21, 1982

था राजेश कुमार सिंह : ग्रथ्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कल ही यह सूचना दी है कि:-

"Information was called for from States/Union Territories for the period from January, 1981 to March, 1982."

यह सूचना शायद कल ही राज्य सभा में दी गई है, लेकिन पता नहीं क्यों लोक-सभा से कुछ नाराज से लग रहे हैं। उन्होंने यह बताने का कष्ट नहीं किया कि प्रण्डर ट्रायल प्रीजनर कितने लोगों की डेथ हुई है। इन्होंने ग्रखबारों में 137 ग्रण्डर ट्रायल डैथ एडिमटेड है, लेकिन इनके ही ब्यान में इन्होंने एक बात भी नहीं कही---

"The details showing the number of undertrial prisoners who died in jails during the period January 1, 1981 to March 31, 1982, are here. The number was 7 for Andhra Pradesh, All the details are there. If you want I can give the circumstances deaths and all that. In the case of Andhra Pradesh the number death is 7; then, bullet injuries during the course of b id to kill and caught-1; other reasons-2. Assam, there are 16 deaths; ....."

पता नहीं यह क्यों नहीं कहना चाहते हैं ग्रौर सदन में कह दिया कि हम मंगा रहे हैं। यदि राज्य सरकारों से सूचना नहीं आई है, तो मंगानी चाहिए और फीगर्स देनी चाहिए कि किस हालत में मृत्यू हुई । कल ही ईन्होंने कहा है कि भ्रण्डर ट्रायल सब्त के स्रभाव में इतनी लम्बी अवधि तक रहते हैं भ्रौर उसके साथ भी अञ्छा वर्ताव नहीं होता है, वे गरीब हैं, निर्धन हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि किस हालत में मृत्यू हुई भौर उसकी सूचना आप को प्राप्त हुई है या नहीं हुई है ? कब तक हो जाएगी ग्रीर क्या ग्राप उसको सदन में रखने का कष्ट करेंगे ?

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: Sir, I did say in Rajya Sabha that Government of India is concerned about the number of undertrial prisoners in different jails in the country. As regards the figures as on 30.6.1981 there were 93,311 undertrials prisoners in different jails in our country. So fa as reports are available with us about 137 under-trial prisoners died between the period January 1981 to March 31, 1982.

श्री राजेस कुमार सिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, क्या ग्रण्डर-ट्रायल प्रीजनर की ग्रवधि ग्रीर इनके रख-रखान के बारे में सुप्रीम कोर्ट के कोई निर्देश हैं ? क्या सरकार ने उस पर ग्रमल किया है या नहीं किया है ग्रौर यदि नहीं किया है, तो क्यों नहीं किया है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जेल में ग्रन्धे और पागल कितने लोग हैं ?

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: There are a number of such cases in different jails but that figure is not available with me at the moment. If you give a separate notice then I will furnish the same. We have already referred the matter to different State Governments to implement Supreme Court's decisions and they are implementing it.

श्री राम विलास पासवान : ग्रध्यक्ष महोदय, मैंने इसी सदन में 28 नवम्बर, 1981 को पूरे उदाहरण के साथ कि म्जफ्फरपूर में जहां कैदियों से डकैतियां करवाई जाती हैं भ्रौर रात को छोटे-छोटे बच्चों के साथ बलात्कार किया जाता है ग्रौर कैंदियों को मारते-मारते मार दिया जाता है-इन सारी घटनाम्रों के संबंध में मामला उठाया था ग्रौर मान-नीय मंत्री महोदय से प्रश्न भी पूछा था। इन्होंने कहा था कि रिपोर्ट मंगा रहे हैं। पुनः मैंने इसी सवाल को लेकर 24 मार्च 1982 को फिर यह मामला इसी सदन में उठाया था ग्रीर उस समय मंत्री

महोदय ने कहा था कि स्पीकर महोदय ने जो शिकायत की थी, उसके बारे में ध्रभी तक स्टेट गवर्नमेंट से कोई रिपोर्ट मुझ को नहीं ग्राई है। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं— क्या उक्त जेल के संबंध में, जिस के बारे में मैंने ग्राप को पुस्तिका भी दे दी है, क्या उस मुजक्फरपुर केन्द्रीय कारा के संबंध में कोई रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हुई तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: Sir, this question is in general form as to the number of deaths of undertrial prisoners in different jails. We have given all the details. About the particular instance he has to give me a separate notice.

श्री राम विजास पासवान : ग्रघ्यक्ष महोदय....

भ्राप्त महोदय : भ्राप लिख कर भेज दीजिये, मैं जवाब दिलवा दूंगा।

श्री राम विलास पासवान : मैंने इसी सदन में इस मामले को 24 नवम्बर को नियम 377 के तेहत उठाया था। उस के बाद इस मामले को 24 मार्च को उठाया था....

ग्र*ायक्ष महोदय* : ग्राप को जवाब दिलवा देंगे, ग्राप मुझे लिख कर दे दीजियेगा।

श्री राम विजास पासवान : मैंने तो दिया हुम्रा है, 377 के तेहत पढ़ा हुम्रा है।

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: The Chief Minister of Bihar has been reminded twice; we are yet to receive the information श्री राम विलाम पासवास : ग्रब तो इस में सप्लीमेंट्री उठता है—मंत्री महोदय को जानकारी है कि इन्होंने दो बार चीफ मिनिस्टर को लिखा है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर का क्या जवाब ग्राया?

**ग्रध्यक्ष महोदय**ः वह कह रहे हैं कि जवाब नहीं ग्राया।

. . . (व्यवधान) . . .

श्री राम विलास पासवान : चीफ मिनिस्टर तो\*\*

MR. SPEAKER: No, it is not allowed. I don't allow this thing. You write to me.

भ्राप की बात मैंने सुन ली है, भ्राप को जवाब दिलवा दूंगा।

श्री राम विलास पासवान : एक क्वेश्चन के ऊपर इतना पैसा खर्च होता है...

श्री मूल चन्द डागः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बड़ा साफ था—क्या सरकार ने राज्य सरकारों से जनवरी, 1981 से मई, 1982 के बीच मरने वाले विचाराधीन बन्दियों की सूची मांगी है ? श्राप कृपा कर यह बतााल इये कि श्राप ने कौन-कौन सी राज्य सरकारों को लिखा है, किस-किस राज्य सरकार ने क्या-क्या कारण दिये हैं, उन के मरने के क्या कारण बतलाये हैं, किस राज्य सरकार ने क्या जवाब दिया है तथा पत्न कब लिखा गया श्रीर जवाब कब श्राया ?

ग्रध्यक्ष महोदय : यह सवाल है या किताब है ? यह लिख कर ग्राना चाहिए था।

MR SPEAKER: You can give notice even for Half-an-hour discussion.

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: I have already said that there are so many reports which are available. Some of the State Governments have already given their reports We are awaiting reports from the States.

DR. SUBRAMANIIAM SWAMY: You will view that sympathetically I think.

SHRI MOOL CHAND DAGA: I don't want this answer; I asked you a specific question. When have you written to the State Governments? What reply have you got? That I want from you.

MR. SPEAKER: I always have sympathy for you. If any Member brings anything to my notice it is always sympathetically considered.

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: May I answer the question? On that point I have already answered that between January, 1981 to March 31, 1982 there are deaths of 137 undertrial prisoners. Not all the States have given us their reports. 8 or 9 States are yet to give us their reports.

Decovering of covered Establishments by Regional Provident Fund Commissioner, Patna

MINISTER OF DEFENCE THE AND HOME AFFAIRS (SHRI R. VENKATARAMAN): I will give the answer to the specific question put by him. Andhra Pradesh, Assam Gujarat, Kerala, Manipur, Orissa, Rajasthan Sikkim, Tamil Nadu, U.P., West Bengal and Delhi have given us their figures. Some of the other States have not given. We are trying to get these figures from them

190. SHRI RAMAVATAR SHAS-TRI: Will the Minister of LABOUR be pleased to lay a statement showing:

MR. SPEAKER: Next question. Shri Sajjan Kumar. Absent. Shri Uttambhai H. Patel Absent.

(a) whether the Regional Provident Fund Commissioner, Patna, (Bihar) has diecovered the covered establishments; and

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I rise on a point of order under Rule 49. You did not allow Calling Attention on the ground that you have admitted a Question. Now, here what has happened in this. Two persons who have tabled these Questions are from the ruling party and they have not turned today. It is a very important question; it is exercising all Armymen throughout the country.

(b) if so, what are the details thereof since July 1980 and what action has been taken against the erring officials?

MR. SPEAKER: I have allowed five questions.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI DHARMAVIR): (a) Yes, Sir.

(b) The Employees' Provident Fund authorities have reported that five establishments, named below have been decovered since July, 1980 to 30-6-82 by the Regional Provident Fund Commissioner. Bihar in the course of proceedings under Section 7A of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952:-

- 1. M/s. Zila Parishad Press, Dhanbad.
- 2. M/s. Annapurna Hotel & Restaurant, Chaibasa
  - 3. M/s. Ahmedia Hotel, Patna.
- 4. M/s. Mineral Industries, Daltonganj.
- 5. M/s. Bihar Bengal Tea Co., Patna.

The Regional Provident Fund Commissioner had decovered the above mentioned establishments in accord-

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: But on this you may please allow a Calling Attention.